देहरादून (उत्तराखण्ड)
गुरुवार 04.12.2025
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों के लिए संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य नहीं। सरकार ने कहा– ऐप पूरी तरह सुरक्षित और इसका उद्देश्य लोगों को साइबर अपराध से बचाना है।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित कृषि गोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कहा– पंतनगर विश्वविद्यालय में हो रहे शोध और नवाचारों का सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है।
- शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिये सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए।
- मुख्य सचिव ने अधिकारियों को विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिकतम और सही उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

निर्णय

केंद्र सरकार ने संचार साथी एप की बढती स्वीकार्यता के बीच मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों के लिए एप को पहले से इन्सटॉल करने को अनिवार्य नहीं करने का फैसला लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नागरिक जब चाहे इस एप को हटा सकते हैं और इस एप का उपायोगकर्ताओं की सुरक्षा के अलावा और कोई कार्य नहीं है। अब तक एक करोड चालीस लाख उपयोगकर्ताओं ने इस एप को डाउनलोड किया है और प्रतिदिन धोखाधडी से सम्बंधित दो हजार घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बीच, लोकसभा में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष के जासूसी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संचार साथी ऐप से जासूसी न तो संभव है और न ही होगी। उन्होंने कहा कि यह एप सुरक्षित है और इसका उद्देश्य साइबर अपराध से लोगों को बचाना है।

उद्घाटन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित कृषि गोष्ठी और कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। लोहिया हेड मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने विश्वविद्यालय, कृषि विभाग और अन्य संस्थानों के स्टॉलों का अवलोकन करते हुए प्रदर्शनी को किसानों के लिए उपयोगी बताया।

कृषि गोष्ठी में पंतनगर विश्वविद्यालय को हरित क्रांति की जन्मस्थली बताते हुए श्री धामी ने कहा कि यहां हो रहे शोध और नवाचारों का सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने किसानों से उन्नत बीजों, आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग से उत्पादन बढ़ाने की अपील की।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कृषि के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम, कुक्कुट और शहद उत्पादन जैसे सहायक व्यवसायों को भी बढ़ावा देने की बात कही।

कार्यक्रम में रीप परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को छह ई–रिक्शा और दो किसानों को अनुदान राशि के चेक दिए गए।

विश्व दिव्यांगता दिवस 2025

देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान और जिला समाज कल्याण विभाग ने संयुक्त रूप से विश्व दिव्यांगता दिवस 2025 मनाया। कार्यक्रम संस्थान के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर छात्रावास ग्राउंड में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और विशिष्ट अतिथि विधायक सविता कपूर शामिल हुए।

कार्यक्रम की शुरुआत विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों से हुई। संस्थान की ओर से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के प्रयासों की जानकारी दी गई। अतिथियों ने दिव्यांगजनों के आत्मविश्वास और उपलब्धियों की सराहना की और समाज में संवेदनशीलता व समावेशन बढ़ाने पर जोर दिया।

इस अवसर पर देहरादून जिले के राज्य स्तरीय पुरस्कार 2025 वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंद दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल भी प्रदान की गई।

घोषणा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अर्द्धसैनिक बलों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए कई घोषणाएं कीं हैं। सीआरपीएफ कैंप मुख्यालय हल्द्वानी में आयोजित पूर्व अर्धसैनिक बल सम्मेलन में श्री धामी ने कहा कि भविष्य में प्रेजिडेंट पुलिस मेडल–गैलेंट्री से सम्मानित अर्द्धसैनिक को 5 लाख रुपये की एकमुश्त अनुदान राशि दी जाएगी।

जिन पूर्व अर्द्धसैनिकों और वीर नारियों के पास अचल संपत्ति नहीं है, उन्हें जीवनकाल में एक बार संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत छूट मिलेगी। राज्य अर्द्धसैनिक बल कल्याण परिषद को सक्रिय किया जाएगा और इसके लिए पुलिस मुख्यालय में कार्यालय उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही सैनिक कल्याण निदेशालय में उपनिदेशक (अर्द्धसैनिक) और बड़े जिलों में सहायक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (अर्द्धसैनिक) के पद स्वीकृत किए जाएंगे। अर्द्धसैनिक बलों के बच्चों की शादी के लिए सैनिकों के समान धनराशि प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड वीरभूमि है और राज्य सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए संकल्प के साथ कार्य कर रही है। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में पूर्व अर्धसैनिक बल कर्मी मौजूद रहे।

छात्र सुरक्षा

विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने चमोली जिले के एक स्कूल में छात्र–छात्राओं से छेड़छाड़ और यौन शोषण की घटना के बात राज्यभर के सभी स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जिला स्तर पर निगरानी व सुरक्षा प्रोटोकॉल सख्ती से लागू करने और राज्य स्तर पर समय–समय पर इसकी समीक्षा करने को कहा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यालयों में छात्र–छात्राओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने बताया कि विभागीय मंत्री के निर्देश पर इस प्रकरण में सख्त कार्रवाई की जा रही है।

बैठक

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में भूमि के सर्वोत्तम उपयोग के लिए गठित अनुशंसा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी लैंड पार्सलों में प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिकतम और सही उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि किसी भी भूमि पर परियोजना शुरू करने से पहले जिलाधिकारी स्तर की साइट चयन समिति उसकी अवस्थिति के अनुसार सबसे उपयुक्त परियोजना तय करे। बड़े लैंड पार्सलों पर कई तरह की परियोजनाएं चलाई जा सकती हैं, इसलिए इनके लिए समग्र योजना तैयार करने पर जोर दिया गया।

औचक निरीक्षक

देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने केदारपुरम स्थित राजकीय नारी निकेतन, बालिका निकेतन, बाल गृह और शिशु सदन का औचक निरीक्षण कर सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने आवास, सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य, साफ–सफाई और शौचालयों की स्थिति की जांच की और संस्थान में रह रही महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों से आवश्यकताओं व समस्याओं की जानकारी ली।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी निवासियों के लिये सुरक्षित, स्वच्छ और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी की जाए। बढ़ती ठंड को देखते हुए उन्होंने महिलाओं, बालिकाओं और शिशुओं को गर्म कपड़े वितरित किये। निकेतन में 173 महिलाएं, 19 बालिकाएं और 23 बच्चे रह रहे हैं जिन्हें आश्रय और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

जिलाधिकारी ने बालिका निकेतन में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बहुउद्देश्यीय खेल मैदान बनाने के निर्देश दिए। शिशु सदन के कमरों में ऑयल हीटर लगाने और नारी निकेतन की सुरक्षा के लिए दो अतिरिक्त होमगार्ड तैनात करने के भी निर्देश दिए

नशा रोकथाम

देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर नशीले पदार्थों की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई जारी रखते हुए एक निजी विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर छात्रों का ड्रग टेस्ट कराया। उपजिलाधिकारी हरिगिर की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने टेस्टिंग के साथ विद्यार्थियों को नशे से स्वास्थ्य और करियर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक भी किया।

जिलाधिकारी ने कहा कि यह अभियान उच्च शिक्षण संस्थानों में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने और नशे की प्रवृत्ति रोकने के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने छात्रों और अभिभावकों से अपील की कि वे ड्रग टेस्टिंग से घबराएं नहीं, इसका उद्देश्य सिर्फ युवाओं को नशे से दूर रखना है। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि टेस्ट में किसी भी छात्र के पॉजिटिव पाए जाने पर संबंधित डीन, कॉलेज स्वामी और जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाएगी।

और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों...

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अर्धसैनिक कल्याण परिषद गठित करने की घोषणा को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण का शीर्षक है – उत्तराखंड में बनेगी अर्धसैनिक कल्याण परिषद, पदक पाने वाले को पांच लाख। अमर उजाला लिखता है – पैरामिलिट्री जवानों के बलिदान होने पर परिवार को मिलेगी 50 लाख की मदद।

परिवहन निगम की बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय को भी सभी समाचार पत्रों ने प्राथमिकता दी है। दैनिक जागरण लिखता है – परिवहन निगम खरीदेगा 250 नयी बसें।

संचार साथी ऐप की खबर को भी सभी समाचार पत्रों ने पहले पृष्ठ पर स्थान दिया है। दैनिक जागरण लिखता है – संचार साथी ऐप नहीं होगा प्री–इनस्टॉल। अमर उजाला का शीर्षक है – स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप पहले से इनस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं, सरकार ने वापस लिया फैसला।